कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

28 जनवरी 2020

मीडिया के उपयोग के लिए

खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार का फोकस खेत से लेकर फूड प्रोसेसिंग व डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर तक आधुनिक और व्यापक नेटवर्क खड़ा करने का- श्री मोदी

गांधी नगर में 4 दिनी वैश्विक आलू सम्मेलन- 2020 का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ

बीते एक दशक में 53 प्र.श. बढ़ा आलू उत्पादन,2020 तक डेढ़ सौ प्र.श. वृदिध की उम्मीद-श्री तोमर

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री तोमर, मुख्यमंत्री श्री रूपाणी व अन्य की भी शिरकत

गांधी नगर (गुजरात)/ नई दिल्ली: गांधी नगर में आयोजित तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन-2020 का शुभारम्भ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार का फोकस खेत से लेकर फूड प्रोसेसिंग और डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर तक एक आधुनिक और व्यापक नेटवर्क खड़ा करने का है। आने वाले 5 वर्षों में सिर्फ सिंचाई और खेती से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रूपए खर्च किए जाना हैं।

28 से 31 जनवरी तक चलने वाले सम्मेलन के शुभारंभ समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला, गुजरात के कृषि मंत्री श्री आर.सी. फाल्दू, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्र, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के निदेशक डॉ. एस. के. चक्रबर्ती के साथ ही बड़ी संख्या में आलू उत्पादक किसान, वैज्ञानिक, नीति-निर्माता, उद्यमी, व्यापारी व 20 देशों के प्रतिभागी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार का फोकस खेत से लेकर फूड प्रोसेसिंग और डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर तक एक आधुनिक और व्यापक नेटवर्क खड़ा करने का है। आने वाले 5 वर्षों में सिर्फ सिंचाई और खेती से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इतना ही नहीं, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेक्टर को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। चाहे इस सेक्टर को 100 परसेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए खोलने का फैसला हो या फिर **पीएम किसान संपदा योजना** के माध्यम से वैल्यू एडिशन और वैल्यू चेन डेवलपमेंट में मदद, हर स्तर पर कोशिश की जा ही है। इस योजना के तहत बहुत ही कम समय में सैकड़ों करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्टस देश में पूरे हो चुके हैं।

श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि खेती की लागत कम हो, किसान का खर्च कम हो। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से, किसानों के अनेक छोटे खर्चों को पूरा करने में मदद मिली है। अब तक 8 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया जा चुका है। इस महीने के शुरुआत में, एक साथ 6 करोड़ किसानों के बैंक खातों में, 12 हजार करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करके एक नया रिकॉर्ड भी बनाया गया है। किसान और उपभोक्ता के बीच के Layers और उपज की बर्बादी को कम करना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए परंपरागत कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि किसानों को ऋण की, टेक्नॉलॉजी की और मार्केट तक एक्सेस आसान हो, इसके लिए Farmer Producer Organizations को प्रमोट किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है

कि आने वाले 5 वर्षों में 10 हज़ार नए FPOs तैयार किए जाएं। यही नहीं e-NAM के रूप में एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट किसानों के बीच में लोकप्रिय हो रहा है। सरकार का जोर कृषि टेक्नॉलॉजी आधारित स्टार्ट अप्स को प्रमोट करने पर भी है ताकि स्मार्ट और प्रिसिजन एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी किसानों के डेटाबेस और एग्री स्टैक का उपयोग किया जा सके। इससे किसानों को पानी, खाद और कीटनाशकों के उचित उपयोग में मदद मिलेगी। इससे लागत की कम होगी और ग्लोबल मार्केट में भारतीय किसानों की ज्यादा भागीदारी भी सुनिश्चित होगी।

समारोह में कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि आलू भारतीय फसल नहीं है बलिक आलू का उद्गम दक्षिण अमेरिका की इंडीज पर्वत श्रृंखलाओं में हुआ था लेकिन लगातार विकास यात्रा के बाद अब वर्तमान में आलू भारत के हर परिवार में, घर-घर की रसोई में प्रवेश कर चुका है। आलू सब्जियों का राजा माना जाता है, इसलिए आलू देश की प्रमुख फसलों- चावल, गेहूं आदि के बराबर महत्व रखता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में दिल्ली में आयोजित दूसरे सम्मेलन के समय देश में आलू का उत्पादन 34.7 मिलियन टन था, जबकि वर्तमान में यह उपज 525 लाख टन तक पहुँच चुकी है। इतना आलू 21.8 लाख हेक्टर क्षेत्र से मिल रहा है। देश में वर्तमान में आलू उत्पादन से 40 लाख किसान जुड़े हुए हैं। साथ ही लाखों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने बताया कि विगत एक दशक में आलू के क्षेत्र में 53% की उत्पादन वृद्धि दर दर्शाई गई है। इसके अलावा वर्ष 2050 तक सालाना 3% की वृद्धि दर अनुमानित है, अर्थात् तब तक आलू उत्पादन में कुल 150 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। देश में सात दशकों में आलू विकास यात्रा के दौरान उत्पादन में 34 गुणा, क्षेत्रफल में 9.3 गुणा व उत्पादकता में 3.7 गुणा वृद्धि हुई है। श्री तोमर ने देश में आलू के उत्पादन में वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से किसानों के परिश्रम के साथ ही केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की दक्षता व अनुसंधान को देते हुए बताया कि यह संस्थान अनुसंधान की दृष्टि से दक्षिण-पश्चिम एशिया में बड़ी भूमिका रखता है। संस्थान के पास आलू के क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा जीन बैंक हैं, जिसमें 4500 जर्मप्लाज्म एकत्र किए गए हैं, जो उन्नतशील प्रजाति विकास के लिए लाभकारी है। संस्थान द्वारा अब तक 62 आलू किस्में विकसित की गई जो विभिन्न जैविक-अजैविक कारकों के प्रति अवरोधी हैं, जिनमें 7 प्रजाति प्रसंस्करणयुक्त चरित्र रखती है। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा 25 प्रजातियों का 3,000 टन प्रजनक बीज उत्पादन प्रति वर्ष किया जा रहा है, जिसकी आपूर्ति विभिन्न अभिकरणों को की जाती है, ताकि वे प्रमाणित बीज तैयार कर किसानों को उपलब्ध करवा सकें।

श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कृषि को उन्नत बनाने, किसानों की आमदनी दोगुनी करने, गरीबों का जीवन स्तर सुधारने, देश में अनुसंधन को बढ़ावा देने के साथ विश्व में देश की "एक राष्ट्र-श्रेष्ठ राष्ट्र" के रूप में पहचान बनाने के हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। खेती का क्षेत्र देश के लिए महत्वपूर्ण है, कृषि व गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होने पर किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता का सामना किया जा सकता है व विजय भी प्राप्त की जा सकती है, इसके मद्देनजर किसानों की आमदनी दोगुनी करने और ग्रामीण विकास हेतु सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। किसानों और वैज्ञानिकों के परिश्रम का परिणाम है कि वर्तमान में देश जहाँ खाद्यान्न, दलहन, दूध व बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, वहीँ तिलहन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, साथ ही हनी के उत्पादन में वृद्धि हेतु हनी मिशन चलाया जा रहा है।